THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) Yes, Sir. A world' Bank assisted Project, namely, Assam Rural Infrastructure and Agricultural Services Project is being implemented from 1995-96 for a period of eight years. Fisheries development is one of the components of the Project and include activities such as fish seed production, development of ponds, community tanks, beels, fisheries research, extension, education, training and open water fisheries development. The estimated cost of the Fisheries component is Rs. 2837.40 lakhs.

(c) As per the information received from the State Government the following expenditure has been incurred during the past three years which is to be reimbursed to the State Government by the World Bank as per the agreed norms:

1995-96	Rs. 17.40 lakhs
1996-97	Rs. 238.48 lakhs
1997-98	Rs. 418.63 lakhs

आयातित गेहूं में खरपतवार के बीज

335. **श्री कपिल सिब्बल** :

श्री राज मोहिन्दर सिह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि पिछले वर्ष आस्ट्रेलिया से जो गेहूं आयात किया गया था उसमें खरपतवार के बीजों की मात्रा बहुत अधिक थी;

(ख) यदि हां, तो आयातित गेहूं में खरपतवार के बीजों की मात्रा कितने प्रतिशत हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि गेहूं में खरपतवार के बीजों की मात्रा बहुत अधिक होना गेहूं की घटिया गुणवत्ता को साबित करता हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या परतिक्रिया हैं और क्या उस संस्थान से, जिसमें घटिया गुणवत्ता का गेहूं भेजा हैं, क्षतिपूर्ति के रूप में हर्जाना प्राप्त हो गया हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) पिछले वर्ष आस्ट्रेलिया से आयातित गेहूं में खरपतवार के बीज पाए गए थे।

(ख) आयातित गेहूं में खरपतवार के बीजों की मात्रा का प्रतिशत वजन के आधार पर 0.06% था।

(ग) विभिन्न भारतीय पत्तनों पर प्राप्त किए गए आस्ट्रेलियाई गेहूं के माल का परीक्षण/विश्लेषण करने पर आयातित गेहूं संविदात्मक विनिर्देशों के अनुरूप और मानव उपयोग के लिए उचित पाया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Urea prices

336. SHRI PREM CHAND GUPTA. Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that this Government has raised the price of Urea by 11%;

(b) whether this will result in saving of subsidy of Rs. 445 crores; and

(c) what will be the impact of this policy on the farm output and prices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The price of Urea has been increased from Rs. 3660. per MT. to Rs. 4000 per M.T. from 29.1.1999, which represents an increase of 9.2%.

(b) On a demand level of 220 lakh M.T. of Urea estimated for 1999-2000, the increase in Urea price is likely to result in a reduction of subsidy of Rs. 748 crores.

(c) The impact of the price rise on farm output and general price level would be negligible.

टर्मिनेटर बीजों के आयात पर प्रतिबंध

337. **श्री ओंकार सिंह लखावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों से टर्मिनेटर बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सरकार की क्या नीति हैं; और

(ख) क्या भारत में टर्मिनेटर बीज तैयार करने के संबंध में देशी/विदेशी अनुसंधानकर्ताओं ने कोई अनुसंधान किया हैं?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) भारत में टर्मिनेटर बीज के कानूनी रूप से प्रवेश की अनुमति नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

विदेशी पौधों के हानिकारक प्रभाव

338. **श्री ओंकार सिंह लखावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से विदेशी पौधों, यथा कांग्रेस ग्रास (पार्थिनियम हिस्ट्रोफारस), लेन्टाना, यूक्लिपटस, विलायती बबूल (प्रोसोपिस) आदि के कुप्रभावों को जानने के लिए कोई अध्ययन करवाया हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन हानिकारक विदेशी पेड़-पौधों के कुप्रभावों को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसके संस्थान कांग्रेस ग्रास, लेन्टाना, यूक्लिपटस और एकेशिया परीक्षणों का कार्य अपने हाथ में लेते हैं।

कांग्रेस ग्रास (पार्थिनियम हिस्ट्रोफोरस) पूरे देश में बंजर भूमि व खाली पड़े के लिए खतरा बन चुकी हैं। यह घास उन फसलों में भी उग जाती हैं जिनके पौधे दूर-दूर रोपे गए होते हैं। कांग्रेस घास की रोकथाम के लिए उपयुक्त संवर्धनात्मक, रासायनिक और जैविक उपायों का मानकीकरण किया गया हैं। फिर भी, इनके कारगर नियंत्रण के लिए सामुदायिक रूप से प्रयास करने की जरूरत हैं।

लेन्टाना एक विदेशी सजावटी झाड़ी हैं और हानिकारक खरपतवार हैं। इससे पर्वतीय क्षेत्र संक्रमित हो गए हैं। इसके कारगर नियंत्रण के लिए रासायनिक एवं जैविक नियंत्रण उपाय अधिक आशाजनक सिद्व हुए हैं।

यूक्लिपटस कागज उद्योग के लिए उपयोगी पौधा हैं जिसे कुछ निश्चित परिस्थितियों में कृषि फसलों के साथ संयुक्त रूप से उगाया जाना चाहिए।

प्रास्पोसिस जूलीफ्लोरा, (विलायती बबूल) ईधन की लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय मरूक्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर में चल रहे काम से ऐसी संभावना का पता चलता हैं कि इस प्रजाति को कांटा रहित बनाकर चारे के पेड़ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता हैं।

Floor price for Copra

339. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government declared the floor price for copra and coconut for the year 1999;

(b) what are the price rates; and

(c) whether Government have made any arrangement to purchase coconut from the peasant at the floor price rate?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) Yes, Sir. The Government has declared the Minimum Support Prices (MSPs) of Fair Average Quality for Milling and Ball Copra at Rs. 3100 per quintal and Rs. 3325 per quintal respectively for the 1999 season. The MSPs declared by the Government for both the varieties of copra during the current season are higher by Rs. 200 per quintal than the MSPs fixed during the previous season.

(c) The National Agricultural Cooperative Marketing Federation (NAFED) has been nominated as central nodal agency for procurement of Copra at the MSPs declared by the Government.

Central assistance for cashew replanting in Kerala

340. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Kerala Government has submitted a project for replanting and productivity improvement of cashew in Kerala seeking financial assistance from the Centre for the implementation of the same; and

(b) if so, the details thereof and Governments reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) During November, 1997 the Government of Kerala submitted a project proposal seeking Central - Assistance of Rs. 107.10